बिहार से फलों और सब्जियों का निर्यात

2076. **श्री रामदेव भंडारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) 30 नवम्बर, 1993 और 1995 तक बिहार से निर्यात किए गए फलों और सब्जियों के संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या फल और सब्जियों के उत्पादक राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान हैं;

(ग) क्या उत्पादन के अनुपात में निर्यात का प्रतिशत संतोषजनक नहीं हैं; और

(घ) क्या सरकार एक विशेष योजना बनाकर निर्यात में वृद्वि करने का विचार रखती हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) निर्यात के राज्यवार आकंड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1993 (अप्रैल से नवम्बर) 1994 (अप्रैल से नवम्बर) तथा 1995 (अप्रैल से सितम्बर, 1995) के दौरान देश से फलों और सब्जियों के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रू. में)
1993 (अप्रैल-नवम्बर, 93)	244.62
1994 (अप्रैल-नवम्बर, 94)	266.26
1995 (अप्रैल-नवम्बर, 95)	229.89

(स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार राज्य का सब्जियों के उत्पादन में प्रथम तथा फलों के मामले में चौथा स्थान था।

(घ) फलों, सब्जियों एवं अन्य कृषिजन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) विशेषीकृत परिवहन एककों की खरीद, पूर्व-प्रशीतन/प्रशीतन भण्डारण सुविधाओं की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देना।

(ii) ग्रेडिंग/प्रसंसकरण केन्द्रों, निलामी मंचों, पकाने वाले/क्युरिंग चैम्बर्स तथा गुणवत्ता जांच उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋण दिए गए।

(iii) उन्नत पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना;

(iv) क्लियरेंस की प्रतीक्षा में पड़ी निर्यात क्षेत्रों के लिए चलन्त प्रकार के प्रशीतन गृहों की स्थापना;

(v) कार्गो बुकिंग के लिए एयर कार्गो सुविधाओं की स्थापना तथा एक छत के नीचे सीमाशुल्क निपटान की सुविधाएं;

(vi) विदेशी बाजारों में स्वीकार्यता में सुधार करने के लिए सड़ने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु वाष्पीकरण सुविधाओं की स्थापना;

(vii) क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियों में भागीदारी;

(viii) निर्यात संवर्धन तथा व्यापार विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ix) कुछ विशेषीकृत ताजें फलों और सब्जियों को 31.3.1996 तक विशेषकृत गंतव्यों तक निर्यात के लिए वायुभाड़ा इमदाद।

Proposal to Liberalise Export-Import Policy

2077. SHRI. K. M KHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to further liberalise export-import policy;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government also propose to liberalise the consumer goods sector;

(d) if so, the details thereof with back-ground;

(e) whether some objective are likely to be achieved from such liberalisation; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (f) Review of the Export and Import Policy is an on-going process and changes in it are made from time to time keeping in view various factors like rising prices, demand and supply position of various commodities, balance of payment position etc.

Storage of Rice for Export by FCI

2078. SHRI. V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India has stored huge quantities of rice for export at Madras, Kakinada and Vizag ports;

(b) details thereof;

(c) when will this rice be exported; and

(d) what are the total exports of foodgrains expected by FCI this year?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) No, Sir. FCI has moved some stock of rice ex-North to various ports for sale to the Private & Public Sector exporters who have purchased rice from FCI and have started exporting rice from Indian Ports.

(d) In view of the comfortable stock position in the Central Pool, Government has authorised the FCI to export/sell for the purpose of export upto 2.5 million tonnes of wheat and 2 million tonnes of fine and superfine rice (since decided to be increased to 3 million tonnes) during the year 1995-96.

Amendment of Child Labour Act

2079. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government is planning to amend the Child Labour Act to eliminate employment of children in hazardous industries; and

(b) if so, the details of changes/ amendments proposed to be made in the Child Labour Act for this purpose?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) A proposal to amend the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, to make it more effective, is under consideration of the Government.

Reduction of Coal linkages for PowerStations

2080. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Standing Linkage Committee for Coal in a meeting held in September, 1995 had reduced coal linkages for all Power Stations;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the percentage of reduction in allocation in the quarter October-December 1995 vis-a-vis July-September 1995 for Power Plants located in West Bengal;

(d) whether the minimum coal stock position as per norms is maintained in the Power Plants after the reduced allocation; and

(e) how long the reduced allocation is expected to continue?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) The overall linkages of coal to the power utilities for the quarter October-December, 1995 were more than the linkages given to them for the quarter July-September, 1995. The present linkages to all power houses in the country have been sanctioned taking into account the recommendations made by Ministry of Power and within the overall quantity earmarked for the power sector.